

गुर नारायण दास और अन्य

बनाम

गुर टहल दास और अन्य

[सैय्यद फ़ज़ल अली और विवियन बोस; न्यायमूर्तिगण]

हिंदू विधि —शूद्र का अवैध पुत्र—पिता की पृथक संपत्ति के विभाजन की मांग करने का अधिकार।

हिंदू विधि के तहत, हालांकि एक शूद्र का अवैध पुत्र अपने पिता के जीवनकाल के दौरान विभाजन के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन वह पिता की मृत्यु के बाद विभाजन के लिए मजबूर कर सकता है यदि पिता अपने संपाशिकों से अलग था और अपने पीछे पृथक संपत्ति तथा वैध पुत्र छोड़ गया हो।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1950 की दीवानी अपील संख्या 104।

9 अप्रैल 1947 दिनांक के पटना उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति मनोहर लाल तथा न्यायमूर्ति मुखर्जी) के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील, जो 1944 की प्रथम अपील संख्या 68 में पारित हुई थी, और जो 23 दिसंबर 1943 को गया स्थित प्रथम अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत द्वारा 1941 की वाद संख्या 4 में दिए गए निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न हुई थी।

गुरुबचन सिंह (मनोहर लाल सचदेव के साथ) अपीलकर्ताओं की ओर से।

एस. बी. जठार उत्तरदाता संख्या 4 के कानूनी प्रतिनिधि की ओर से।

1952. मई 16. न्यायालय का निर्णय दिया गया

फ़ज़ल अली; न्यायमूर्ति द्वारा—यह अपील विभाजन के एक वाद से उत्पन्न हुई है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था लेकिन अपील पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया था। मामले के महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

एक रामबिलास दास के 2 पुत्र थे, बुद्धप्रकाश दास और नंदकिशोर दास। नंदकिशोर दास के कई पुत्र थे, जिनमें से वादी, गुरटहल दास उनके अवैध पुत्रों में से एक था। वर्तमान वाद गुरटहल दास द्वारा 4 व्यक्तियों के विरुद्ध लाया गया था, अर्थात् गुरटहल दास और जय नारायण दास, नंदकिशोर दास के पुत्र, शिवटहल दास जिसे नंदकिशोर दास का एक अवैध पुत्र बताया गया था, और श्रीमती रामभोली कुएर, जो नंदकिशोर दास के पुत्रों में से एक नानकशरण दास की पत्नी थी। एक अन्य व्यक्ति, कुलदीप दास, जो नंदकिशोर के भाई बुद्धप्रकाश दास की बेटी का बेटा था, वाद की संस्थापना के बाद इसमें शामिल हुआ और उसे पांचवें प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया। दूसरे प्रतिवादी, जय नारायण दास की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी सूरत कुएर को अभिलेख पर लाया गया।

वादी का मामला यह था कि बुद्धप्रकाश दास और नंदकिशोर दास एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे, और बुद्धप्रकाश दास की मृत्यु अपने भाई नंदकिशोर के साथ संयुक्त अवस्था में बिना किसी पुरुष संतान के हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण संयुक्त परिवार की संपत्ति उन (नंदकिशोर) पर आ गई। बाद में, वादी और प्रतिवादियों के बीच संपत्तियों के प्रबंधन और उपभोग को लेकर विवाद उत्पन्न हुए, जिसने वादी को विभाजन के लिए वर्तमान वाद दायर करने के लिए विवश किया। वादी ने आरोप लगाया कि पक्षकार शूद्र थे और फकीरों के नानक शाही संप्रदाय से संबंधित थे, और वह तथा तीसरा प्रतिवादी शिवटहल दास, एक उपपत्नी से नंदकिशोर दास के दासीपुत्र थे, और जय नारायण दास तथा गुरनारायण दास भी एक अन्य उपपत्नी से नंदकिशोर के दासीपुत्र थे।

वाद का मुख्य रूप से प्रथम प्रतिवादी गुरटहल दास और श्रीमती सूरत कुएर द्वारा निम्नलिखित दलीलों पर विरोध किया गया था:— पहली यह कि, वाद विभाजन के वाद के रूप में चलने योग्य नहीं था, क्योंकि वादी का उन संपत्तियों पर कभी कब्जा नहीं था जिनका उसने विभाजन मांगा था; दूसरी यह कि, प्रतिवादियों का परिवार शूद्र नहीं बल्कि द्विज था और एक अवैध पुत्र विभाजन के लिए वाद दायर नहीं कर सकता था; तीसरी यह कि, प्रतिवादी वादी और शिवटहल दास के साथ संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य नहीं थे; चौथी यह कि, श्रीमती रामभोली कुएर नानकशरण दास की विधवा नहीं थी; और पांचवीं यह कि, वादी और शिवटहल दास नंदकिशोर दास के पुत्र नहीं थे। श्रीमती रामभोली कुएर का मामला यह था कि पक्षकार द्विज थे न कि शूद्र, और प्रतिवादी संख्या 5, कुलदीप दास ने भी इसी आशय की दलील दी और आगे आरोप लगाया कि बुद्धप्रकाश दास, नंदकिशोर दास से अलग थे, कि हालांकि उन्होंने संपत्तियों का विभाजन मीट्स एंड बाउंड्स द्वारा नहीं किया था, लेकिन वे उपज को आधा-आधा बांटते थे, और वह बुद्धप्रकाश दास की बेटी के बेटे के रूप में संपत्तियों के अपने हिस्से पर काबिज था और उन्हें विभाजन का विषय नहीं बनाया जा सकता था। शिवटहल दास ने वादी के दावे का समर्थन किया।

विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए वाद को खारिज कर दिया कि, अन्य बातों के अलावा, (1) चूँकि वादी किसी भी संपत्ति के संयुक्त कब्जे में नहीं था, इसलिए विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं था, (2) पक्षकार शूद्र थे, (3) बुद्धप्रकाश दास और नंदकिशोर दास संयुक्त थे न कि अलग, (4) वादी के पास वाद का कोई कारण नहीं था, और (5) शिवटहल दास यह साबित नहीं कर पाए थे कि वह नंदकिशोर के पुत्र थे। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, वादी ने पटना उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, और कुलदीप दास ने इस निष्कर्ष का विरोध करते हुए एक प्रति-आपत्ति दायर किया कि बुद्धप्रकाश अपने भाई नंदकिशोर के साथ संयुक्त थे।

उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और यह माना कि (1) पक्षकार शूद्र थे न कि द्विज, (2) बुद्धप्रकाश की मृत्यु अपने भाई नंदकिशोर से अलगाव की स्थिति में हुई थी, और (3) स्वामित्व की घोषणा के लिए किसी वाद की आवश्यकता नहीं थी और वादी द्वारा पर्याप्त न्यायालय शुल्क का भुगतान न करना उसे उपयुक्त राहत दिए जाने के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2, गुरटहल दास और जय नारायण दास, नंदकिशोर दास के वैध पुत्र थे। उपरोक्त निष्कर्षों पर, उच्च न्यायालय ने एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जिसमें निर्देश दिया गया कि शिवटहल दास को छोड़कर वादी और प्रतिवादियों को संपत्तियों का अलग-अलग आवंटन किया जाना चाहिए।

प्रथम अपीलकर्ता की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष कि पक्षकार शूद्र थे, सही नहीं था और इसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यह तर्क विफल होना चाहिए, क्योंकि हमें इस न्यायालय की उस सुस्थापित प्रथा से हटने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है जिसमें विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, यह निष्कर्ष कि पक्षकार शूद्र हैं, काफी हद तक मौखिक साक्ष्यों पर आधारित है, और उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने अपने निष्कर्ष पर पहुँचते समय उन परीक्षणों की अनदेखी नहीं की है जो इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आधिकारिक निर्णयों की एक श्रृंखला में निर्धारित किए गए हैं कि क्या कोई व्यक्ति द्विजों से संबंधित है या शूद्र समुदाय से।

अगला प्रश्न जिस पर हमारे समक्ष बहुत गंभीरता से बहस की गई, वह यह था कि क्या बुद्धप्रकाश दास और नंदकिशोर दास संयुक्त थे या अलग। इस प्रश्न पर, दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन हमारे समक्ष मौजूद साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक

विचार करने के बाद, हमारा झुकाव उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के साथ सहमत होने की ओर है, जिन्होंने संपूर्ण साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि बुद्धप्रकाश दास की मृत्यु नंदकिशोर से अलगाव की स्थिति में हुई थी। यहाँ विचारण न्यायाधीश के निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा जिसमें उन्होंने इस प्रश्न पर साक्ष्यों का सारांश प्रस्तुत किया है:-

"अभिलेख पर मौजूद मौखिक साक्ष्यों से, यह काफी स्पष्ट है कि बुद्धप्रकाश एक अलग घर में रहते थे और फसलें प्राप्त करते थे। इस प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 5 कुलदीप दास) ने 1936 की चौकीदारी रसीद (पंजिका संख्या 283) प्रदर्श बी (2) और प्रदर्श सी 1 (आकलन पंजिका की प्रति जिसमें बुद्धप्रकाश के नाम पर संख्या 284 दर्शाई गई है) भी दाखिल की है जो यह दिखा सकती है कि संभवतः बुद्धप्रकाश अलग चौकीदारी कर का भुगतान कर रहे थे। प्रतिवादी संख्या 5 ने ए-1, ए-5, ए-4, ए-6, ए-10 और ए-12 के रूप में चिह्नित कुछ पत्र भी दाखिल किए हैं, जो न केवल यह दिखाते हैं कि यह प्रतिवादी, प्रतिवादी के परिवार से संबंधित है, बल्कि यह भी कि उसे समय-समय पर अनाज और धन दिया जाता था। लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाता है कि बुद्धप्रकाश और नंदकिशोर के बीच विभाजन हुआ था या प्रतिवादी संख्या 5 कभी बुद्धप्रकाश के उत्तराधिकारी के रूप में किसी संपत्ति पर काबिज हुआ था। बेशक, उनके समर्थन में कुछ मौखिक साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन साक्ष्यों पर विचार करने और उन्हें तौलने के बाद, मुझे नहीं लगता कि नंदकिशोर से बुद्धप्रकाश का अलगाव सिद्ध हुआ है। प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि बिहार रिपोर्ट, खंड 4 (1937-38) प्रिवी काउंसिल पृष्ठ 302 में सूचित किए गए फैसले के आलोक में परिस्थितियों पर विचार करने से प्रतिवादी के मामले को समर्थन मिलेगा क्योंकि खतियान (प्रदर्श जी1 और जी2) में बुद्धप्रकाश और नंदकिशोर का परिभाषित हिस्सा था। मैं इस बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता से सहमत होने के

लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यह दिखाने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं है कि बुद्धप्रकाश या उनके बाद भी कुलदीप दास ने किसी संपत्ति के उपभोग का अलग से विनियोग किया, या कभी बुद्धप्रकाश ने अलगाव का कोई इरादा दिखाया। मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि यदि बुद्धप्रकाश अलग हुए होते, तो कम से कम उनकी मृत्यु पर प्रतिवादी संख्या 5 ने विवादित संपत्तियों से अपनी आय की एक खाता बही रखी होती, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वह एक दूर स्थान पर रहते थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने कभी संपत्ति की देखभाल करने या अपने कथित सह-साझेदारों से हिसाब मांगने की परवाह की।"

साक्ष्यों का यह सारांश सबसे पहले यह दर्शाता है कि दोनों भाई अलग-अलग घरों में रहते थे, दूसरी बात यह कि वे अलग-अलग चौकीदारी कर का भुगतान करते थे, और तीसरी बात यह कि बुद्धप्रकाश समय-समय पर नंदकिशोर से अनाज और पैसा प्राप्त किया करते थे। विचारण न्यायाधीश ने यह भी देखा है कि खतियान, प्रदर्श जी 1 और जी 2 दोनों भाइयों के परिभाषित हिस्सों को दर्ज करते हैं, लेकिन मुद्रित अभिलेख से पता चलता है कि प्रदर्श जी 1 और जी 2 मात्र लगान-रसीदें हैं। चूंकि खतियान मुद्रित नहीं था, इसलिए हमने मूल अभिलेख मंगवाया और पाया कि खतियान की प्रविष्टियाँ, जो प्रदर्श एफ 1 और एफ 2 हैं, विचारण न्यायालय के निर्णय में सही ढंग से दर्ज की गई हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो निष्कर्ष हमने बताए हैं, वे प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों को अन्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की तुलना में अधिक समर्थन देते हैं, और ऐसा होने के कारण, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाना चाहिए। हम प्रदर्श-ए श्रृंखला के कई पत्रों से बहुत प्रभावित हुए, जिन्हें दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वास्तविक पाया गया है। हमारे समक्ष पत्रों की प्रामाणिकता पर हमला किया गया था, लेकिन हमें विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पलटने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है। इनमें से एक पत्र प्रदर्श ए-10 में,

नंदकिशोर दास ने 12 जून, 1934 को कुलदीप को लिखते हुए कहा है कि वह 25 मन चावल, 7 मन खेसारी और पचहत्तर रुपये भेज रहे थे और फिर जोड़ते हैं: मेरे पास सारा लिखा हुआ हिसाब है, जिसे तुम्हारे आने पर समझाया जाएगा और तुम आने पर अपने हिस्से का उचित हिसाब देना। एक अन्य पत्र, प्रदर्श ए-12 में, जो नंदकिशोर द्वारा 15 अक्टूबर, 1936 को कुलदीप को लिखा गया था, पूर्ववर्ती (नंदकिशोर) कहता है: "मैंने तुम्हें अपने हिस्से के हिसाब के समायोजन के लिए कई बार लिखा, लेकिन तुमने अब तक ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें अपने हिस्से के हिसाब की जाँच करने के लिए आने हेतु लिखता हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। यदि तुम्हारे पास समय हो, तो एक दिन के लिए आओ और हिसाब समायोजित करवा लो और जो तुम्हारा बकाया निकले उसे ले लो"। हमें ऐसा लगता है कि यदि पक्षकार वास्तव में शब्द के कानूनी अर्थ में संयुक्त होते, तो हिसाब की जाँच करने और उन्हें समायोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता और उपज या एकत्र किए गए धन में कुलदीप के हिस्से का कोई संदर्भ नहीं होता। जिस उचित निष्कर्ष पर पहुँचा जाना चाहिए वह यह है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 5 के गवाहों ने कहा है, कि यद्यपि मीट्स एंड बाउंड्स द्वारा कोई विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन दोनों भाई स्थिति में विभाजित थे और अपने संबंधित हिस्सों के अनुसार संपत्तियों के उपभोग का आनंद लेते थे। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से कई गवाहों की जांच की गई, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत ज्ञान से कहा है कि दोनों भाई अलग-अलग घरों में रहते थे, उनका भोजन अलग था और उपज उनके बीच आधी-आधी बांटी जाती थी। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भाइयों के अलगाव के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाना चाहिए।

अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई तीसरी दलील इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या वादी केवल भरण-पोषण का हकदार है या नंदकिशोर दास द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में हिस्से का। एक शूद्र के अवैध पुत्र के अधिकारों पर मिताक्षरा, अध्याय 1, धारा 12 में विचार किया गया है,

जिसका शीर्षक है "शूद्र की संपदा के मामले में, दासी से उत्पन्न पुत्र के अधिकार"। इस पाठ पर प्रिवी काउंसिल द्वारा *वेल्थैयाप्पा बनाम नटराजन*<sup>1</sup> के मामले में पूरी तरह से विचार किया गया था और उससे प्राप्त निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया गया था:-

"लॉर्डशिप की राय है कि एक निरंतर उपपत्नी से उत्पन्न शूद्र के अवैध पुत्र को पुत्र का दर्जा प्राप्त है, और वह परिवार का एक सदस्य है; उसे दिया गया विरासत का हिस्सा केवल भरण-पोषण के बदले में नहीं है, बल्कि पुत्र के रूप में उसके दर्जे की मान्यता में है; जहाँ पिता ने कोई पृथक संपत्ति और कोई वैध पुत्र नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने संपाधिकों के साथ संयुक्त था, वहाँ अवैध पुत्र उनके हाथों में मौजूद संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग करने का हकदार नहीं है, लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में वह उस संपत्ति में से भरण-पोषण पाने का हकदार है।"

कानून के इस कथन में, जिससे हम सहमत हैं, तीन अन्य सुस्थापित सिद्धांतों को जोड़ा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं: पहला यह कि, अवैध पुत्र जन्म से अपने पिता की संपदा में कोई हित प्राप्त नहीं करता है और इसलिए वह अपने पिता के जीवनकाल के दौरान उनके विरुद्ध विभाजन की मांग नहीं कर सकता है; दूसरा यह कि, अपने पिता की मृत्यु पर, अवैध पुत्र वैध पुत्र (पुत्रों) के साथ उत्तरजीविता के अधिकार के साथ पिता की पृथक संपदा में एक सह-दायिक के रूप में उत्तराधिकारी होता है और वैध पुत्र (पुत्रों) के विरुद्ध विभाजन लागू करने का हकदार होता है; और तीसरा यह कि, एक वैध और एक अवैध पुत्र के बीच विभाजन होने पर, अवैध पुत्र को उस हिस्से का केवल आधा हिस्सा मिलता है जो उसे तब मिलता यदि वह एक वैध पुत्र होता।

यह प्रतीत होता है कि ऊपर प्रतिपादित दूसरा प्रस्ताव मिताक्षरा पाठ के निम्नलिखित अंश से लिया गया है:-

---

1 ए.आई.आर. 1931 पी.सी.

"किन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात, यदि विवाहित पत्नी से पुत्र हों, तो ये भाई दासी-पुत्र को आधे हिस्से का भागीदार बनने दें।"

इसलिए, यदि अवैध पुत्र अपने पिता के वैध पुत्र के साथ सह-सायाद है, तो यह अनिवार्य रूप से निष्कर्ष निकलता है कि वह वैध पुत्र के विरुद्ध विभाजन की मांग करने का हकदार है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यद्यपि अवैध पुत्र पिता के जीवनकाल के दौरान विभाजन लागू नहीं कर सकता है, और यद्यपि वह उस स्थिति में विभाजन की मांग करने का हकदार नहीं है जहाँ पिता ने कोई पृथक संपत्ति और कोई वैध पुत्र नहीं छोड़ा है बल्कि वह अपने संपाशिकों के साथ संयुक्त था, वह वर्तमान जैसे मामले में विभाजन लागू कर सकता है, जहाँ पिता अपने संपाशिकों से अलग था और उसने पृथक संपत्ति तथा वैध पुत्र छोड़े हैं।

अपीलकर्ताओं की ओर से रखा गया अंतिम बिंदु यह था कि वादी उन संपत्तियों पर कब्जा नहीं रखता है जो वाद का विषय हैं, इसलिए वह विभाजन के लिए वाद कायम नहीं रख सकता। यह तर्क मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि वादी निस्संदेह संपत्तियों में सह-धारक है और जब तक अपवर्जन और बेदखली का तर्क न दिया जाए और उसे सिद्ध न किया जाए, जो कि इस मामले में नहीं है, वह विभाजन का हकदार है।

इस प्रकार, अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिए गए सभी बिंदु विफल हो जाते हैं, लेकिन एक संबंध में, उच्च न्यायालय की डिक्री में संशोधन किया जाना चाहिए। इसे समझने के लिए, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अपने लिखित बयान के कंडिका 8 और 11 में दिए गए निम्नलिखित कथनों का संदर्भ लेना होगा:

"8. कि यह प्रतिवादी जागीर और काश्त भूमि में आधा हिस्सा रखता है। महंत बुध प्रकाश दास उत्तर की ओर वाले घर में अलग रह रहे थे जो उन्हें आवंटित किया गया था और

दक्षिणी हिस्सा नंदकिशोर दास के तख्ते को आवंटित किया गया था, जो कि सबसे छोटा घर था और 2 हवेलियों में विभाजित था।

11. कि इस प्रतिवादी का जागीर और काश्त भूमि से संबंधित अनुसूची सी और डी के तहत दी गई संपत्तियों में आठ आना हिस्से से कोई लेना-देना नहीं है, जो कि न्यायसंगत रूप से नंदकिशोर दास की थी और उन अनुसूचियों में दर्ज संपत्तियों से कोई सरोकार नहीं है।"

कंडिका 11 की शब्दावली काफी अस्पष्ट है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह स्वीकार किया कि उक्त प्रतिवादी का अनुसूची सी और डी के अलावा अन्य अनुसूचियों में दी गई संपत्तियों में किसी भी हित का कोई दावा नहीं था। कंडिका 8 और 11 का ऐसा अर्थ होने के कारण, डिक्री में यह प्रावधान होना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 5 केवल अनुसूची सी और डी में दी गई संपत्तियों में हिस्से का हकदार होगा और अन्य अनुसूचियों में दी गई संपत्तियों में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इस संशोधन के अधीन, उच्च न्यायालय की डिक्री की पुष्टि की जाती है, और यह अपील खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

*अपील खारिज।*

अपीलकर्ताओं के एजेंट: *नौनित लाल।*

चौथे उत्तरदाता के कानूनी प्रतिनिधि के एजेंट: *आर. एन. साचथे।*

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।